



दक्षिण भारत राष्ट्रमत

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಮತ | ಹಿಂದಿ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ | बेंगलूरु और चेन्नई से एक साथ प्रकाशित



5 नौकरी के बहाने जमीन छीनने की साजिश : रविशंकर प्रसाद

6 बिहार चुनाव : मुद्दों एवं मूल्यों से दूर भागती राजनीति

7 चित्रांगदा सिंह की तबीयत बिगड़ी, पोस्ट शेयर कर बताया, 'जल्द ही दौड़ने लगूंगी'

फ़र्स्ट टेक

यूरोपीय संघ ने रूस पर कई और आर्थिक प्रतिबंध लगाए
ब्रसेल्स/एपी। यूरोपीय संघ (ईयू) ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन युद्ध समाप्त करने का दबाव बढ़ाने के लिए बृहस्पतिवार को रूस पर कई और आर्थिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। इससे पहले बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के तेल उद्योग के खिलाफ कई प्रतिबंधों की घोषणा की थी। हालांकि, रूसी अधिकारियों और सरकारी मीडिया ने पश्चिमी देशों के दंडात्मक उपायों को काफी हद तक अप्रभावी बताते हुए खारिज कर दिया।

मिशन मंडेला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com



कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

गठबंधन

वैचारिक मतभेद भले हो, अवसर को सब करते वंदन। बिन सत्ता के हर दल वाले, नेता करते प्रतिपल क्रंदन। खुदगर्जी का चक्रव्यूह रच, खूब लगाते घिस-घिस चंदन। कुर्सी के बंधन में फँस कर, करते हैं सब नव गठबंधन॥

विपक्षी गठबंधन 'गठबंधन' नहीं, बल्कि 'लठबंधन' (अपराधियों का गठबंधन) है : मोदी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि बिहार में 'जंगलराज' पर अगले 100 साल तक चर्चा होगी और विपक्ष अपने कुकृत्यों को छिपाने की कितनी भी कोशिश कर ले, जनता उसे माफ नहीं करेगी। तेजस्वी यादव को बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किए जाने के बीच राजद-कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन



'गठबंधन' नहीं, बल्कि 'लठबंधन' (अपराधियों का गठबंधन) है क्योंकि दिल्ली और बिहार के इसके सभी नेता जमानत पर बाहर हैं। मोदी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं से यह सुनिश्चित करने को कहा कि बुजुर्ग लोग युवाओं को

'जंगलराज' के दौरान हुए अत्याचारों के बारे में जानकारी दें। मोदी का इशारा उस समय की ओर था जब बिहार में राजद प्रमुख लालू प्रसाद मुख्यमंत्री थे। ऑडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 'मेरा बूथ सबसे मजबूत: युवा संवाद' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में 'जंगलराज' को लोग अगले 100 साल तक नहीं भूलेंगे और विपक्ष अपनी कर्तूतों को छिपाने की कितनी भी कोशिश कर ले, जनता उसे माफ नहीं करेगी। मोदी ने कहा, "बिहार के सभी युवाओं से कहूंगा कि वे हर बूथ पर युवाओं को इकट्ठा करें

और उस क्षेत्र के बुजुर्गों को बुलाकर 'जंगलराज' की पुरानी कहानियां सबको बताएं।" उन्होंने एक भाजपा कार्यकर्ता से बातचीत करते हुए कहा कि देश में विकास का एक 'महायज्ञ' चल रहा है, तथा केंद्र और बिहार में स्थिर सरकार के कारण चोतरफा काम हो रहा है। मोदी ने कहा, "बिहार में हर क्षेत्र में, हर दिशा में काम हो रहा है। अस्पताल बन रहे हैं, अच्छे स्कूल स्थापित हो रहे हैं और नए रेल मार्ग विकसित किए जा रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि देश और बिहार में एक स्थिर सरकार है। जब स्थिरता होती है, तो विकास तेज होता है।

कपाट



उत्तराखंड में स्थित विश्वप्रसिद्ध उच्च गढ़वाल हिमालयी धामों केदारनाथ और यमुनोत्री के कपाट बृहस्पतिवार को भैयादूज के पावन पर्व पर परंपरागत पूजा पाठ और विधि-विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए।

गगनयान मिशन का 90 प्रतिशत विकास कार्य पूरा : इसरो प्रमुख

बेंगलूरु। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने बृहस्पतिवार को कहा कि गगनयान मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा है और लगभग 90 प्रतिशत विकास कार्य पूरा हो चुका है। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। नारायणन ने मिशन की प्रगति के बारे में एक सवाल के जवाब में कहा, गगनयान मिशन पर बहुत अच्छी तरह से काम जारी है। वास्तव में, जब आप गगनयान मिशन के बारे में बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि

बहुत सारे तकनीकी विकास होने हैं - रॉकेट का मानव-रेटिंग प्रमाणन होना है, कक्षीय मॉड्यूल विकसित करना है, और पर्यावरण नियंत्रण सुरक्षा प्रणाली विकसित करनी है। फिर चालक दल की सुरक्षा की प्रणाली, पैराशूट प्रणाली और फिर, निश्चित रूप से, मानव-केंद्रित उत्पाद आते हैं। वह तीन से पांच नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन

(ईएसटीआईसी-2025) की प्रचार गतिविधियों के अवसर पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) कहा कि लगभग 90 प्रतिशत विकास कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा, अब चालक दल वाले मिशन पर जाने से पहले तीन मानवरहित मिशन पूरे करने होंगे और हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। पहले मानवरहित मिशन में, व्योममित्र उड़ान भरने जा रहा है और हम 2027 की शुरुआत तक मानवयुक्त मिशन पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं।

भारत मानवता, निष्पक्षता तथा तटस्थता के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध : अनुराग ठाकुर

हमीरपुर (हिप्र)/भाषा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत की मानवीय भागीदारी की दिशा संप्रभुता, अहस्तक्षेप और 'नैतिक जिम्मेदारी' के सिद्धांतों से तय होती है, और भारत मानवता, निष्पक्षता तथा तटस्थता के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध है।



भाजपा की ओर से बृहस्पतिवार को जारी एक बयान के अनुसार, पूर्व केंद्रीय मंत्री और हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से सांसद ठाकुर ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अंतर-संसदीय

संघ (आईपीयू) की 151वीं बैठक में यह टिप्पणी की। बयान के मुताबिक, 170 देशों के सांसदों की सभा में भारत के सांसदों का प्रतिनिधित्व करते हुए ठाकुर ने संघर्ष और आपदाओं की बदती घटनाओं के बीच बहुपक्षीय सहयोग में गिरावट और मानवीय सहायता निधि में कमी के प्रति आगह किया। उन्होंने आईपीयू की आम चर्चा में संकट के समय में मानवीय मानकों को कायम रखना और मानवीय कार्रवाई का समर्थन करना विषय पर भारत का पक्ष प्रस्तुत किया।

रक्षा मंत्रालय ने 79,000 करोड़ रुपए के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी

नई दिल्ली/भाषा। रक्षा मंत्रालय ने सेना की लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नाम मिसाइलों, युद्धक जहाजों और इलेक्ट्रॉनिक खुरफिया एवं निगरानी प्रणालियों सहित 79,000 करोड़ रुपए के हथियार और सैन्य साजो-सामान खरीदने के प्रस्तावों को बृहस्पतिवार को मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद (डीएसी) की बैठक में खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद खरीद पर यह दूसरा बड़ा फैसला है। पांच अगस्त को 67,000 करोड़ रुपए की खरीद परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि डीएसी ने लगभग 79,000 करोड़ रुपए की कुल लागत के विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी।

शोक संदेश



उम्र
103 वर्ष

देह परिवर्तन
23.10.2025

स्व. श्रीमती सुमतीबाई भंडारी

धर्मपत्नी : संघवी स्व. श्री भबूतमलजी भंडारी (मरुधर में सायला)

अत्यंत दुःख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारी पूजनीय मातुश्री श्रीमती सुमतीबाई भंडारी का देह परिवर्तन दि. 23.10.2025, गुरुवार को हो गया है। विधि के विधान के आगे हम सब नतमस्तक है।

शोकाकुल

भतीज : धीरजकुमार, अशोककुमार, हीराचंद, रवीकुमार

पुत्र-पुत्रवधु : चम्पालाल - भंवरीदेवी, पौत्र-पौत्रवधु : प्रतीक - वैशाली

पुत्री-दामाद : कमलाबाई - स्व. जवेरचंदजी दांतेवाड़िया, गुलाबीदेवी - प्रकाशकुमारजी बंदामुथा

पौत्री-दामाद : निकिता - राहुलकुमारजी दांतेवाड़िया, पूजा - विधांतकुमारजी दुगड़

दोहित्र : महेन्द्रकुमार, राजेशकुमार, प्रतीककुमार, त्रिनेशकुमार

पड़दोहित्र-पड़दोहित्री : रीत, रिन्ती, जयकुमार एवं समस्त भंडारी परिवार, मरुधर में सायला, बेंगलूरु

निवास स्थान : संघवी चंपालाल भवुतमलजी भंडारी

नं. 8, प्रतीक विला, रेल्वे पैरल रोड, नेहरुनगर, बेंगलूरु-20 मो : 9844198341, 9845900700, 9900002050

पीहूर पक्ष : धनराजजी, बाबुलालजी, घेवरचंदजी, सोहनलालजी, जयंतीलालजी, मदनलालजी, महेन्द्रकुमारजी, फतेहचंदजी, नरपतराजजी, अनिलकुमारजी एवं समस्त संघवी परिवार (आलासन)



CORPORATION - Bengaluru

नोट : उठावणा तक बैठक निवास स्थान पर रखी गई है।

GST बचत उत्सव

अब हमारी
सेहत का ख्याल
रखना हुआ सस्ता

GST राहत लाई खुशियों की सौगात

बुजुर्गों का स्वास्थ्य और सम्मान हो रहा सुनिश्चित

₹50,000 के
सालाना हेल्थ प्रीमियम पर
₹9,000 तक की बचत

सीनियर सिटीजन
हेल्थ इंश्योरेंस
हुआ सस्ता

₹3,000 तक की
मासिक मेंबरशिप पर
लगभग ₹400 की बचत

स्वास्थ्य जांच
उपकरणों
पर बचत

योग और
मेडिटेशन सेवाओं
पर बचत

ग्लूकोमीटर ₹70
थर्मामीटर ₹50
BP मॉनिटर ₹90
तक सस्ते

एक बार के खर्च पर
₹16,000 तक
की बचत

“नागरिक देवो भवः” के जिस मंत्र के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म में इसकी साफ झलक दिखाई देती है।”

- नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

GST - बेहतर और आसान

CBIC 15502/13/00040/2526

देव दर्शन

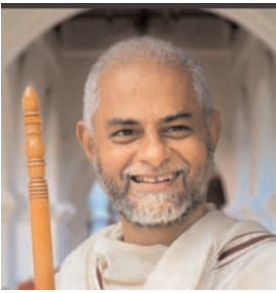
दक्षिण भारत राष्ट्रमत



बेंगलूरु के शाकम्भीपीय ब्राह्मण समाज शिवाजीनगर के महिला मंडल की सदस्याओं ने दीपावली व नववर्ष के उपलक्ष्य में बस द्वारा विभिन्न मंदिरों के दर्शन कर पूजा की। सदस्याओं ने बन्नरघट्टा रोड स्थित आशापुरा माता मंदिर, खाट्ट श्याम मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, शेवाद्रिपुरम स्थित इस्कॉन जगन्नाथ मंदिर व बालाजी मंदिर के दर्शन किए तथा समाज के लिए खुशहाली की कामना की।

मनोभावों को प्रभावित करने में चित्रों की अहम भूमिका : आचार्य अरिहंतसागरसूरी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com



बेंगलूरु। शहर के माधवनगर जैन संघ में भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण कल्याणक के उपलक्ष्य में आयोजित चित्र प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर प्रवचन में आचार्य श्री अरिहंतसागर सूरीशरजी ने कहा कि शब्द की तरह चित्र का भी मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक संदेशयुक्त चित्र व्यक्ति को सकारार्थ की प्रेरणा देते हैं। आज सोशल मीडिया के युग में चारों ओर हिंसा,

जीवन चरित्र से लोगों को चित्रों के माध्यम से रूबरू कराया जाए जिससे उन्हें गुणों और संस्कारों की प्रेरणा मिले।

प्रदर्शनी के आयोजक वासुपूज्य संस्कार वाटिका के सदस्य अहम वेदमुथा ने बताया कि प्रदर्शनी के चित्र भगवान महावीर स्वामी की जीवन को जानने में बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए सरल एवं प्रभावशाली माध्यम साबित हो रहे हैं। गुरुवार को आचार्यश्री की निश्रा में मुम्बई के मुमुक्षु भव्य शाह की होने वाली दीक्षा की आमंत्रण पत्रिका लिखी गई।

अश्लीलता और अपराध के दुश्मनों की भरमार ने लोगों के मनोभावों और व्यवहार में विपरीत परिवर्तन लाने में अहम भूमिका निभाई है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में यह अत्यंत आवश्यक है कि महापुरुषों के

आंध्र सरकार नकली शराब के उत्पादन, बिक्री को ‘संस्थागत’ बना रही है : वाईएसआर प्रमुख

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com



अमरावती/बाधा। युवजन श्रमिक रायथू काग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने बृहस्पतिवार को आंध्र प्रदेश सरकार पर नकली शराब के उत्पादन, वितरण और बिक्री को संस्थागत बनाने का आरोप लगाया। ताडेपल्ली में वाईएसआरसीपी केंद्रीय कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि तेलंगु देशम पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के माध्यम से राज्यव्यापी अवैध शराब का रैकेट चला रही है, जिसमें नकली शराब कारखाने स्थापित करना भी शामिल है। रेड्डी ने कहा, आज रायथू में देखें कि अवैध और नकली शराब संस्थागत तरीके से बेची जा रही है। उन्होंने कहा कि वेदपा नेता एवं कार्यकर्ता अपनी खुदरा शराब दुकानों के माध्यम से इसकी बिक्री कर रहे हैं। विपक्षी नेता के अनुसार, अवैध शराब दुकानों (बेट्टे शांप्स) की नीलामी गांवों में पुलिस सुरक्षा में हो रही है, जबकि अनधिकृत परमिट के जरिये नकली

शराब ऊंची कीमतों पर बेची जा रही है। रेड्डी ने दावा किया कि अवैध शराब से सरकार को राजस्व घाटा हो रहा है और जन स्वास्थ्य को खतरा हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि परवाड़ा, पलाकोल्लू, अलमपुरम, एलुरु, रेपल्ले और नेल्लोर में नकली शराब की इकाइयां पाई गई हैं। उन्होंने कथित नकली शराब बनाने के लिए ज्वट की गई सामग्री की तस्वीरें दिखाई, जिनमें स्टिकर, लेबल, सील, बोतलों, डिब्बे, कार्टन और कई अन्य उपकरण शामिल हैं। वाईएसआरसीपी प्रमुख अनुसार, संगठित तरीके से नकली शराब बनाने, वितरित करने और बेचने की विरासत नायडू और उनके बेटे नारा लोकेश की है। इसके अलावा, रेड्डी ने कहा कि लूट के माल के बंटवारे को लेकर आंतरिक मतभेद के कारण कथित नकली शराब गिरोह का पर्दाफास हुआ।

ट्रेन सुरक्षा प्रणाली ‘कवच’ का अभी वैश्विक मानकों पर खरा उतरना बाकी: हिताची रेल इंडिया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com



नई दिल्ली/बाधा। रेलवे समाधान प्रदान करने वाली कंपनी हिताची रेल इंडिया के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि भारत की स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली ‘कवच’ का वैश्विक मानकों पर खरा उतरना अभी बाकी है। ‘कवच’ स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली है। रेल मंत्रालय का कहना है कि यह अत्यधिक प्रौद्योगिकी-प्रधान प्रणाली है और उच्चतम सुरक्षा प्रमाणन के साथ आती है। ट्रेन के चालक द्वारा ब्रेक न लगा पाने की स्थिति में ‘कवच’ स्वचालित रूप से ब्रेक लगाकर उसे निर्दिष्ट गति सीमा के भीतर ट्रेनों को चलाने में सहायता करता है। यह खराब मौसम के दौरान ट्रेन सुरक्षा को भी बढ़ाता है। भारतीय रेलवे नेटवर्क पर कवच प्रणाली को बड़े पैमाने पर तैनात किए जाने की प्रक्रिया में जापानी कंपनी हिताची के भागीदार न होने के बारे में पूछे जाने पर हिताची रेल एस्टीएस इंडिया के पूर्णकालिक निदेशक और कंपनी

प्रतिनिधि मनोज कुमार कृष्णप्पा ने कहा कि कवच अभी वैश्विक मानकों के अनुरूप नहीं है। कृष्णप्पा ने कहा, ‘‘हम कवच समाधानों का हिस्सा नहीं बने क्योंकि यह भारतीय रेलवे के लिए एक स्वदेशी जरूरत है। मुझे बहुत खुशी है कि कई भारतीय कंपनियां कवच पर काम कर रही हैं। हिताची इंडिया को इस बात पर गर्व है कि यह एक भारतीय उत्पाद है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह अभी वैश्विक मानकों की जरूरतों के अनुरूप एक स्थापित प्रौद्योगिकी नहीं है। इसलिए हम प्रतीक्षा कर रहे हैं और इस पर नजर रखे हुए हैं।’’ रेल मंत्रालय ने वर्ष 2018-19 में कवच प्रणाली की शुरुआत की थी। हालांकि देश भर के कई रेल

खंडों पर यह प्रणाली पहले ही लगाई जा चुकी है, लेकिन इसे अभी चालू किया जाना बाकी है। रेल मंत्रालय का दावा है कि कवच प्रणाली यूरोपीय ट्रेन नियंत्रण प्रणाली (ईटीसीएस) के स्तर-2 के बराबर है। कवच के आगमन से पहले हिताची रेल एस्टीएस इंडिया ने वर्ष 2016 में भारत की पहली उच्च गति वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस में ट्रेन सुरक्षा एवं चेतावनी प्रणाली (टीपीडब्ल्यूएस) को लागू किया था। कृष्णप्पा ने कवच प्रणाली के टीपीडब्ल्यूएस से बेहतर होने के बारे में पूछे जाने पर कहा, ‘‘टीपीडब्ल्यूएस कहीं एक बेहतर प्रौद्योगिकी है।... भारत ने मुख्य रूप से लागत और अन्य कारणों से टीपीडब्ल्यूएस को नहीं अपनाया।’’

संवैधानिक शासन प्रणाली में अदालतों की सक्रिय और अपरिहार्य भूमिका है : प्रधान न्यायाधीश गवई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/बाधा। जनता के विश्वास को न्यायपालिका की ‘‘सबसे मूल्यवान संपत्ति’’ बताते हुए प्रधान न्यायाधीश बी. आर. गवई ने बृहस्पतिवार को कहा कि संवैधानिक शासन प्रणाली और संविधान के कार्यक्षेत्र को पूरा करने में न्यायालयों की सक्रिय एवं अपरिहार्य भूमिका है।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि संवैधानिक शासन में न्यायालयों की शायद सबसे स्थायी भूमिका कानून के शासन में जनता के विश्वास को बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय, भले ही अलोकप्रिय हों, निष्पक्षता और नैतिक साहस को प्रतिबिंबित करने वाले होने चाहिए। भूटान की

चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए न्यायमूर्ति गवई ने रॉयल इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, थिम्पू में जिम्मे सिये वांगचुक (जेएसडब्ल्यू) स्कूल ऑफ लॉ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में वक्तव्य दिया। उन्होंने ‘‘न्यायालय और संवैधानिक शासन’’ विषय पर अपने संबोधन में न्यायालयों की सक्रिय भूमिका सहित कई पहलुओं पर प्रकाश डाला। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मैं आपको और ज्यादा उदाहरणों से बोझिल नहीं करूंगा, लेकिन एक व्यापक बिंदु पर जोर देना चाहता हूं: किसी भी देश की अदालतों की संवैधानिक शासन प्रणाली में और संविधान के कार्यक्षेत्र को पूरा करने में एक सक्रिय एवं अपरिहार्य भूमिका होती है।’’ उन्होंने कहा कि न्यायपालिका इस प्रक्रिया में न केवल संवैधानिक पाठ की व्याख्या करके, बल्कि संस्थाओं



के बीच मध्यस्थ, मौलिक अधिकारों के संरक्षक और पर्यावरण एवं सामूहिक कल्याण के रक्षक के रूप में भी योगदान देती है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘इस प्रकार अदालतों की एक विशिष्ट स्थिति है: उन्हें संवैधानिक संतुलन बनाए रखने का कर्तव्य सौंपा गया है, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि न्याय की भावना शासन में व्याप्त रहे।’’ उन्होंने कहा कि न्यायिक प्राधिकार अंततः बल प्रयोग पर नहीं, बल्कि

नैतिक वैधता पर आधारित है जो नागरिकों का न्यायपालिका की निष्पक्षता, स्वतंत्रता और शुचितता में विश्वास और भरोसा है। न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि अदालतें पारदर्शिता, तर्कसंगत निर्णयों और संवैधानिक सिद्धांतों के निरंतर पालन के माध्यम से यह विश्वास अर्जित करती हैं। उन्होंने कहा, ‘‘प्रत्येक निर्णय, चाहे वह अलोकप्रिय ही क्यों न हो, उसमें निष्पक्षता और नैतिक साहस परिलक्षित होना चाहिए। जब नागरिकों को यह विश्वास हो कि न्याय बिना किसी भय या पक्षपात के होगा, तो संपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था की वैधता मजबूत होती है।’’ प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘जनता का विश्वास न्यायपालिका की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। यही वह चीज है जो न्यायिक निर्णयों को मात्र कानूनी आवेदों से सामाजिक

विवेक के साधन में बदल देती है।’’ उन्होंने कहा कि इस विश्वास को बनाए रखकर, अदालतें न केवल कानून की व्याख्या कर सकती हैं, बल्कि लोकतंत्र की संरक्षक भी बनती हैं, जो संविधान की पूरी तरह रक्षा करती हैं। न्यायमूर्ति गवई ने कहा, ‘‘अंत में, न्यायपालिका की भूमिका का एक पहलू है जिस पर अक्सर उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए: संवैधानिक साक्षरता को बढ़ावा देने और संवैधानिक मूल्यों के बारे में जनता की समझ विकसित करने की जिम्मेदारी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘न्यायपालिका संविधान की संरक्षक और नैतिक चेतना दोनों के रूप में कार्य करती है। इसकी भूमिका व्याख्या से परे है। यह राज्य के अंगों के बीच नाजुक संतुलन बनाए रखकर संवैधानिकता की जीवंत भावना को मूर्त रूप देती है।’’

साल 2024 में डिजिटल भुगतान की हिस्सेदारी 99.7 प्रतिशत रही : आरबीआई रिपोर्ट

मुंबई/बाधा। देश में कलेंडर वर्ष 2024 के दौरान भुगतान प्रणाली में मात्रा के हिसाब से डिजिटल भुगतान लेनदेन 99.7 प्रतिशत और मूल्य के हिसाब से 97.5 प्रतिशत रहा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की बृहस्पतिवार को जारी रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि यह प्रवृत्ति 2025 की पहली छमाही में भी जारी रही।



रिजर्व बैंक की जून, 2025 की अर्धवार्षिक भुगतान प्रणाली रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में हाल के वर्षों में भुगतान प्रणाली में काफी तेजी से वृद्धि हुई है। देश में भुगतान प्रणाली कई प्रकार के तरीकों का समूह है, जो उपयोगकर्ताओं की विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। इनमें कागज आधारित साधन जैसे चेक और डिजिटल भुगतान प्रणाली दोनों शामिल हैं। डिजिटल भुगतान

प्रणालियों में एनईएफटी, आईआईएमपीएस, एनएसीएन, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड भुगतान उपकरण और यूपीआई शामिल हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सभी प्रकार के भुगतान में वृद्धि हो रही है, सिवाय कागज आधारित साधनों के। मूल्य के हिसाब से चेक कुल लेनदेन का केवल 2.3 प्रतिशत हिस्सा है। रिपोर्ट के अनुसार, साल 2019 में कुल 3,248 करोड़ भुगतान हुए थे, जो 2024 तक बढ़कर 20,849 करोड़ हो गए।

इसी अवधि में कुल भुगतान की रकम 1,775 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2,830 लाख करोड़ रुपए हो गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि जून, 2025 को समाप्त छमाही में 12,549 करोड़ लेन-देन हुए। इसमें 1,572 लाख करोड़ रुपए की राशि शामिल है। भुगतान में लगभग सारी वृद्धि डिजिटल भुगतान लेनदेन के कारण हुई है।

एआई सामग्री पर नियंत्रण करना सरकार का मकसद नहीं, पारदर्शिता जरूरी : मेइटी सचिव

नई दिल्ली/बाधा। सरकार ने बृहस्पतिवार को स्पष्ट किया कि कृत्रिम मेधा (एआई) के जरिये बनाई गई या संशोधित सामग्री पर स्पष्ट लेबल लगाना अनिवार्य करने के पीछे उसका मकसद ऑनलाइन सामग्री को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (मेइटी) सचिव एस कृष्णन ने एआई-निर्मित सामग्री पर मंत्रालय की तरफ से जारी प्रस्तावों के मसौदे के बारे में यह बात कही। कृष्णन ने कहा, हम केवल यह चाहते हैं कि सामग्री पर स्पष्ट निशान हो कि यह एआई द्वारा निर्मित है या नहीं। सरकार ने आईटी नियमों में संशोधन के प्रस्ताव के मसौदे में कहा है कि 50 लाख या अधिक उपयोगकर्ताओं वाले बड़े सोशल मीडिया मंचों (फेसबुक और यूट्यूब) को भी एआई सामग्री की सत्यता जांचने और उचित तकनीकी उपायों से इसे चिन्हित करने की जिम्मेदारी निभानी होगी। इन नियमों में एआई-निर्मित सामग्री का निशान लगाना, दृश्यता और मेटाडेटा एम्बेडिंग जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं ताकि एआई एवं कृत्रिम ढंग से बनी सामग्री को वास्तविक मीडिया से अलग पहचाना जा सके।



युवाओं की तकदीर बदलने के लिए सरकार ठोस प्रयास कर रही : भगवंत मान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com



मोरिंडा (रूपनगर)/बाधा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनकी सरकार युवाओं को नौकरी मांगने वालों की बजाय नौकरी देने वाला बनावर उनकी तकदीर बदलने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। यहां शहीद सुब्बदार मेधा सिंह स्कूल ऑफ एमिनेंस के विद्यार्थियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पंजाब में शैक्षिक क्रांति के एक नए युग की शुरुआत की है। उन्होंने एक बयान में कहा कि यह क्रांति छात्रों को प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार करके और उन्हें जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम बनाकर वांछित परिणाम दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने 2022 में ‘‘शिक्षा क्रांति’’ शुरू की है ताकि पंजाब के बच्चों को अपने सपनों को हकीकत में बदलने और जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद मिल

सके। मान ने दावा किया कि अतीत पर नजर डालने पर यह देखना वास्तव में निराशाजनक है कि कैसे दौषपूर्ण नीतियों के कारण गरीब बच्चों को शिक्षा के उनके अधिकार से वंचित किया गया। हालांकि, मुख्यमंत्री ने कहा कि अब राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में ‘‘क्रांतिकारी’’ कदम उठाए हैं, जिनकी देशभर में व्यापक सराहना हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में 231.74 करोड़ रुपए के निवेश से 118 ‘‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’’ स्थापित किए जा रहे हैं। मान ने कहा कि इन स्कूलों को वंचित बच्चों के उच्चल भविष्य की दिशा में एक उल्लेखनीय शुरुआत माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में विद्यार्थियों को निःशुल्क वर्दी उपलब्ध कराई जा रही है।

‘आप’ ने भाजपा पर छठ के लिए यमुना की सफाई का ‘नाटक करने’ का आरोप लगाया

नई दिल्ली/बाधा। आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकारों पर त्योहार से पहले स्वच्छता का ‘‘भ्रम’’ पैदा करने के लिए उत्तर प्रदेश की पूर्वी नहर का पानी यमुना नदी की ओर मोड़ने का बृहस्पतिवार को आरोप लगाया। सत्तारूढ़ पार्टी ने हालांकि, इस आरोप को खारिज कर दिया। ‘आप’ की दिल्ली इकाई के प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की पूर्वी नहर से पानी यमुना नदी में मोड़ने का कदम बिहार विधानसभा चुनावों से पहले पूर्वांचली मतदाताओं को लुभाने का एक राजनीतिक प्रयास है। भारद्वाज ने कहा, ‘‘भाजपा का झूठ पकड़ा गया है। छठ से पहले यमुना के प्रदूषण को कम करने के लिए भाजपा ने उत्तर प्रदेश की नहर का पानी रोक दिया। हरियाणा की भाजपा सरकार ने हथिनीकुंड से उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए आने वाले सारे पानी को यमुना में मोड़ दिया ताकि कुछ दिनों के लिए यह साफ दिखाई दे।’’ उन्होंने कहा कि भाजपा हटा देने वाले रसायनों का उपयोग करके झग को हटाया जाएगा।



पीडीपी राज्यसभा चुनाव में नेकों का समर्थन करेगी : महबूबा मुपती

श्रीनगर/बाधा। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने बृहस्पतिवार को सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेका) को एक दिन बाद होने वाले राज्यसभा चुनाव में समर्थन देने की घोषणा की। पार्टी प्रमुख महबूबा मुपती ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘हमने नेका को समर्थन देने और उनके उम्मीदवारों को वोट देने का फैसला किया है।’’ उन्होंने कहा कि भाजपा को जीत से दूर रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। महबूबा ने कहा, ‘‘यह पार्टी (नेका) इसकी हकदार नहीं है, लेकिन हमें फासीवादी ताकतों को दूर रखने के व्यापक उद्देश्य के लिए अपना समर्थन देना होगा।’’ उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में समर्थन के लिए नेकों के अनुरोध पर पार्टी नेतृत्व और उसके विधायकों के साथ चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया। पीडीपी प्रमुख ने कहा कि नेका अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने उनसे फोन पर बात की और उनकी पार्टी के समर्थन का अनुरोध किया। नेका के राज्यसभा उम्मीदवार शम्मी ओबेरॉय ने भी समर्थन मांगने के लिए महबूबा से उनके आवास पर बुधवार को मुलाकात की थी।



उत्तराखंड सरकार अग्निवीर बनने के इच्छुक युवक-युवतियों को देगी निशुल्क प्रशिक्षण

देहरादून/बाधा। उत्तराखंड सरकार सेना में अग्निवीर बनकर देश की सेवा करने के इच्छुक युवक-युवतियों को भर्ती पूर्व निशुल्क प्रशिक्षण देगी। अधिकारियों ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार कर ली है तथा यह प्रशिक्षण राज्य के सभी 13 जिलों में दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों विभाग को युवाओं को अग्निवीर भर्ती के लिए प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए थे ताकि वे उत्तराखंड की महान सैन्य परंपरा के अनुसार सेना में अपना करियर बना सकें। अग्निवीर भर्ती पूर्व प्रशिक्षण हेतु इच्छुक युवक-युवतियों के लिए उत्तराखंड का मूल या स्थायी निवासी होना अथवा राज्य में किसी संस्थान में अध्ययनरत या सेवावर होना अनिवार्य है। इसके अलावा, प्रशिक्षण हेतु हाईस्कूल परीक्षा 45 प्रतिशत या उससे अधिक अंक के साथ उत्तीर्ण होना तथा प्रत्येक विषय में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 16 वर्ष से अधिक आयु होना जरूरी है।

मुंबई में बहुमंजिला व्यावसायिक इमारत में आग लगी, 17 लोग दम घुटने से पीड़ित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/बाधा। मुंबई के जोशेश्वरी उपनगर में बृहस्पतिवार सुबह एक 13 मंजिला व्यावसायिक इमारत में आग लगने से 17 लोग धुएं की चपेट में आ गए जिससे उनका दम घुटने लगा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि जिन लोगों ने दम

घुटने की शिकायत की थी उनमें से नौ का इलाज पास के नगर निगम द्वारा संचालित एम्बुसी अस्पताल में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आठ अन्य ने चिकित्सीय सहाय के विरुद्ध अस्पताल से छुट्टी ले ली। उन्होंने बताया कि गांधी स्कूल के पास जेएनएस बिजनेस सेंटर में सुबह करीब 10.50 बजे आग लग गई, जिससे शीशे के सामने घना काला धुआं फैल गया। अधिकारी ने बताया कि आग को बुझाने का काम जारी है। इमारत की नींवों से 13वीं



मंजिल तक आग की लपटें फैल गईं। आग चौथी और 13वीं मंजिल के बीच इलेक्ट्रिक डबट में भी फैल गई। एक दमकल अधिकारी ने

बताया कि कम से कम 12 दमकल गाड़ियां और अन्य अभिशमन उपकरण मौके पर लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि दमकल कर्मियों

ने सीढ़ियों और हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म सीढ़ियों का उपयोग करके विभिन्न मंजिलों से दो महिलाओं सहित कुल 27 लोगों को बचाया। अधिकारी ने बताया कि आग की लपटें बिजली के तारों और छतों, दरवाजों, खिड़कियों, बिजली और ऐसी की नलियों और फर्नीचर तक ही सीमित थीं। अधिकारी ने बताया कि 11वीं से 13वीं मंजिल तक के कार्यालयों में धुआं भर गया और दमकल कर्मियों ने उदा आने-जाने के लिए शीशे तोड़ दिए।

एसडीएम को थप्पड़ मारने की घटना में पेट्रोल पंप कर्मचारी गिरफ्तार

जयपुर/दक्षिण भारत। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के जसवंतपुरा इलाके में आरएसएस अधिकारी को थप्पड़ मारने की घटना के सिलसिले में पेट्रोल पंप के तीन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। यह घटना मंगलवार को उस समय हुई जब प्रतापगढ़ में उप-जिलाधिकारी के रूप में तैनात छोटू लाल शर्मा की पेट्रोल पंप के एक कर्मचारी के साथ बहस हो गई। यह पेट्रोल पंप सीएनजी भी बेचता है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएसएस) के अधिकारी छोटू लाल शर्मा की कार से पहले एक अन्य कार में सीएनजी भरने को लेकर हुए विवाद के बाद यह बहस शुरू हुई। पुलिस के अनुसार शर्मा ने कर्मचारी द्वारा दूसरी कार में सीएनजी भरने पर आपत्ति जताते हुए तर्क दिया कि उनकी कार में पहले सीएनजी भरी जानी चाहिए क्योंकि वह पहले पहुंचे थे। इस दौरान एक अन्य पेट्रोल पंप कर्मचारी ने बीच-बचाव किया लेकिन एसडीएम ने उसे थप्पड़ मार दिया। इसके बाद कर्मचारी ने भी पलटवार करते हुए एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। यह पूरी घटना पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बुधवार को इस झगड़े का वीडियो सामने आया। पुलिस ने बताया कि घटना के सिलसिले में पेट्रोल पंप के तीन कर्मचारियों दीपक माली, प्रभु लाल कुमावत और राजा शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।

जोधपुर में तीन साल की बच्ची का अपहरण करके उससे दुष्कर्म किया

जोधपुर/दक्षिण भारत। राजस्थान में जोधपुर जिले के बिलाड़ा में घर के बाहर खेल रही तीन साल की बच्ची का अपहरण करके उससे दुष्कर्म किये जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने बाजार बंद रखा। पुलिस ने बताया कि एक व्यक्ति जो कथित तौर पर लड़की को मोटरसाइकिल पर ले गया था, वह बाद में उसे उसके घर के बाहर छोड़ कर भाग गया। पुलिस ने बताया कि बच्ची के रोने की आवाज सुनकर उसके परिवार के सदस्य दौड़कर बाहर आए और उसे परेशान हालत में पाया। उसने बताया कि परिजन लड़की को अस्पताल ले गए, जहां गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे जोधपुर शहर के एक अन्य अस्पताल में रेफर कर दिया। पुलिस ने भरतपुर जिले के 22 वर्षीय जेसीबी ऑपरेटर साजिद को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया। बिलाड़ा क्षेत्राधिकारी पदमदान रत्न ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन्हें बीच, घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने करबे का बाजार बंद कर दिया तथा अपराधी को कड़ी सजा देने की मांग की।

पिता की अंत्येष्टि के खर्च को लेकर विवाद में बड़े भाई की कुल्हाड़ी से हत्या

जयपुर। राजस्थान के बाड़मेर जिले में युवक ने अपने पिता के क्रिया कर्म के खर्च को लेकर हुए विवाद के बाद अपने बड़े भाई की कथित तौर पर कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। बीजराड़ के थानाधिकारी मंगाराम ने बताया कि यह घटना बुधवार देर रात नवातला गांव में हुई जब गणेशा राम (35) और उसके छोटे भाई किशना राम (30) के बीच अपने पिता के अंतिम संस्कार पर खर्च हुए पैसों को लेकर तीखी बहस हुई। बहस बढ़ने पर किशना राम ने अपने बड़े भाई पर कुल्हाड़ी से हमला किया। उसने भाई के सिर के पिछले हिस्से पर वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। थानाधिकारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और सबूत जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीमों को मौके पर बुलाया गया है। पुलिस के अनुसार किसान गणेशाराम अपने छोटे भाई और बुजुर्ग मां के साथ रहता था। उसकी पत्नी का 2019 में निधन हो गया था और दंपति के कोई संतान नहीं थी। आरोपी का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के लिए अलग-अलग टीमें तैनात की गई हैं।

‘विकसित राजस्थान’ दस्तावेज में राज्य को 4,300 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान सरकार ने अपना ‘विकसित राजस्थान2047’ दृष्टिकोण पत्र जारी किया है। अधिकारियों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के अनुसार तैयार यह दस्तावेज राजस्थान का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित करेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में तैयार इस दस्तावेज (विजन डॉक्यूमेंट) का लक्ष्य राज्य को चार स्तंभों – कृषि, उद्योग, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा – पर आधारित 4,300 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य तय किया है। उनके इस लक्ष्य में अपना योगदान देने की दिशा में मुख्यमंत्री शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार विकसित राजस्थान2047 के संकल्प को लेकर काम कर रही है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में विकसित राजस्थान2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। इसके अनुसार युवा, महिला, किसान और गरीब को केन्द्र में



रखते हुए यह दस्तावेज विकसित भारत2047 की आकांक्षाओं के अनुरूप राजस्थान को प्रमुख रूप से आर्थिक, साक्षरता, सुलभ स्वास्थ्य, सतत जल प्रबंधन, स्मार्ट शहरीकरण, पर्यावरण संरक्षण एवं युवा व महिला सशक्तीकरण के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में योजनाबद्ध रूप से कार्य किया जा रहा है। इसके तहत राज्य सरकार ने वर्ष 2047 के दूरगामी लक्ष्य को हासिल करने के लिए चरणबद्ध रूप से विकास की रूपरेखा बनाई है। इसके लिए वर्ष 2030, 2035 और 2040 के मध्यावधि लक्ष्य भी तय किए गए हैं। इस प्रकार विभिन्न चरणों में

आकार लेते हुए राज्य के विकास की तस्वीर पूर्ण होगी। विकास के इस दस्तावेज को प्रमुख रूप से चार थीम और 13 क्षेत्रों में बांटा गया है। इसमें तय लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों द्वारा कार्ययोजना तैयार की गई है। कार्ययोजना का वित्तीय आवश्यकताओं के अनुसार हर वर्ष आकलन किया जाएगा और सतत निगरानी एवं मूल्यांकन कर रूपरेखा तैयार की जाएगी। इससे हर विभाग की तय लक्ष्य के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित होगी और विकास कार्य निर्बाध रूप से पूरे हो सकेंगे।



भजनलाल शर्मा ने पूर्व उपराष्ट्रपति शेखावत को श्रद्धांजलि अर्पित की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बृहस्पतिवार को यहां पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत की श्रद्धांजलि अर्पित की। शर्मा ने

विद्याधर नगर स्थित स्मृति स्थल पहुंचकर पूर्व उपराष्ट्रपति एवं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत की जयंती पर उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में शर्मा ने कहा कि शेखावत ने राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत होकर देश व प्रदेश की मजबूती

और जनसेवा के माध्यम से गरीब के उत्थान का कार्य किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व उपराष्ट्रपति ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से प्रेरित होकर राजस्थान में अंत्योदय योजना के माध्यम से अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को सहारा देकर आगे बढ़ाने का काम किया था।

साथ ही, महात्मा गांधी एवं बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के विचारों को भी आगे बढ़ाया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी, सांसद मदन राठौड़ व मंजू शर्मा व विभिन्न जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।



राष्ट्र के लिए विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास शिक्षा के मंदिरों में ही संभव है : मदन दिलावर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। बालोतरा जिले के सिणधरी स्थित विद्या भारती द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर में आज नवनिर्मित भवन का लोकार्पण संतो के सानिध्य में बड़े धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम में लोकार्पण एवं भामाशाह सम्मान समारोह का

आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश के कई गणमान्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, उद्योग राज्य मंत्री के. के. बिश्रौड़, एवं विधायक हमीर सिंह भायल उपस्थित रहे। समारोह में भामाशाह समन्द्र

सिंह नौसर सहित संस्थान को सहयोग देने वाले अन्य भामाशाहों को श्रीराम चित्र और श्रीरामचरितमानस भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राष्ट्र के लिए विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास शिक्षा के मंदिरों में ही संभव है। उन्होंने राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा किए जा रहे नवाचारों को लेकर

विस्तार से चर्चा की और कहा कि राज्य सरकार शिक्षा को संस्कारों से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि विद्यालय केवल पढ़ाई का स्थान नहीं, बल्कि संस्कार, सेवा और राष्ट्रभक्ति की भावना का केंद्र हैं। कार्यक्रम में संत-महात्माओं ने भी आशीर्चन दिए और विद्यार्थियों को जीवन में अनुशासन, सेवा और संस्कार अपनाने की प्रेरणा दी।

राष्ट्रीय स्तर पर महिला एवं बाल विकास की विभिन्न योजनाओं में लगतार बेहतरीन प्रदर्शन किया : दिया कुमारी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। उपमुख्यमंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी के निर्देशन में राजस्थान महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर महिला एवं बाल विकास की विभिन्न योजनाओं में लगतार बेहतरीन प्रदर्शन किया जा रहा है। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा में

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की निष्ठा व समर्पण का परिणाम है। महेन्द्र सोनी ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रवार रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान ने इस माह के लिए निर्धारित 81,01,730 लक्ष्यों के मुकाबले 88,93,346 उपलब्धियाँ दर्ज की हैं, जिससे राज्य की कुल उपलब्धि दर 114.12 प्रतिशत रही। उन्होंने बताया कि इस उत्कृष्ट प्रदर्शन से राजस्थान ने अपने 41 जिलों और 62,321



आंगनबाड़ी केंद्रों के सहयोग से पोषण माह को एक जनआंदोलन के रूप में सफल बनाया है। राष्ट्रीय स्तर पर गुजरात 1 1 5 7 4 प्रतिशत के साथ

नम्बर वन और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में भी नम्बर वन रहने के बाद और राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के चौथे स्थान के पिछले प्रदर्शन को और बेहतर प्रदर्शन करते हुए इस बार (17 सितम्बर से 16 अक्टूबर 2025) राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस उत्कृष्ट प्रदर्शन पर महिला एवं बाल विकास विभाग (निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं) को बधाई दी है। महिला एवं बाल विकास शासन सचिव महेन्द्र सोनी ने बताया कि उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के निर्देशन में महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रभावी रणनीति, जिला प्रशासन के समन्वित प्रयासों, तथा

प्रथम, राजस्थान 114.12 प्रतिशत के साथ द्वितीय तथा छत्तीसगढ़ 108.30 प्रतिशत के साथ तृतीय स्थान पर है। निदेशक आईसीडीएस वासुदेव मालावत ने यह संकल्प दोहराया कि आने वाले महीनों में भी पोषण से जुड़ी गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा ताकि राजस्थान कुपोषण मुक्त राज्य बनकर देश के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर सके। पोषण माह 2025 के दौरान राजस्थान के विभिन्न जिलों में जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता, गृह भ्रमण, पौष्टिक आहार वितरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परामर्श, और सुपोषित राजस्थान के लक्ष्य को साकार करने हेतु अनेक अभिनव गतिविधियाँ आयोजित की गईं।



पिता का वैक्स स्टेच्यू देखकर भावुक हुई दीया कुमारी : नाहरगढ़ वैक्स म्यूजियम में प्रदर्शित हुई ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह की प्रतिमा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। नाहरगढ़ की ऊंची पहाड़ियों पर बसे जयपुर वैक्स म्यूजियम में गुरुवार का दिन भावनाओं से भरा हुआ था। मौका था महावीर चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह की जयंती का, और इस अवसर पर उनकी वैक्स प्रतिमा का लोकार्पण किया गया।कार्यक्रम में उनकी बेटी और राजस्थान की उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दीया कुमारी ने अपने पिता की वैक्स मूर्ति का अनावरण किया। जैसे ही परदा हटाया गया, वहां मौजूद सभी लोगों ने तालियों से स्वागत किया, जबकि दीया कुमारी की आंखें नम हो उठीं। उन्होंने कहा यह मेरे लिए गर्व और

भावनाओं से भरा क्षण है। मेरे पिताजी केवल हमारे परिवार के नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के गौरव थे। उनका यह वैक्स स्टेच्यू देखकर ऐसा लगा मानो वे मेरे सामने खड़े हैं। मैं जयपुर वैक्स म्यूजियम और उन सभी काशीगरों की आभारी हूँ जिन्होंने इतनी सजीव प्रतिमा बनाई। ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह न केवल जयपुर राजघराने के उत्तराधिकारी थे, बल्कि भारतीय सेना के एक बहादुर योद्धा भी थे। उन्होंने 1971 के भारत-पाक युद्ध में विशेष साहस का प्रदर्शन किया था, जिसके लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनका योगदान केवल सैन्य क्षेत्र तक सीमित नहीं था उन्होंने जयपुर की सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाई।

बांसवाड़ा में मोटरसाइकिलों की टक्कर में तीन लोगों की मौत

जयपुर। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में पिछली रात दो तेज रफ्तार मोटरसाइकिलों की आमने-सामने की टक्कर हो जाने से तीन लोगों की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उसने बताया कि यह दुर्घटना बुधवार रात सदर थानाक्षेत्र के भगतपुरा गांव में हुई। सदर थाना प्रभारी बुधराम बिश्रौड़ ने बताया कि तेज गति से चल रही मोटरसाइकिलें आपस में भिड़ गईं। उन्होंने कहा, तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर में मोटरसाइकिलें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान रमेश कटारा, खोमा चरपोटा और हासन के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक दोनों घायलों को पहले एमजी अस्पताल ले जाया गया और बाद में उन्हें उदयपुर पहुंचाया गया। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए।



आपका विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति : बेदम

जयपुर। भाई दूज पर आयोजित ऐतिहासिक मेले में हुए शामिल, ‘पसोपा से नगला ढूंढी’ सड़क की दी महत्वपूर्ण सांगातपसोपा (डीग)। भाई दूज के पावन पर्व पर, नगर विधानसभा क्षेत्र के ऐतिहासिक गाँव पसोपा में आयोजित विशाल मंदिर मेले एवं सामाजिक कार्यक्रम में आज अभूतपूर्व जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे राजस्थान सरकार के गृह, गोपालन, पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्य विभाग राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेदम के स्वागत में जनसमूह का उत्साह वरम पर था। मेला परिसर, आस-पास के भवन और छतें खचाखच भरी हुई थीं, जो मंत्री के प्रति जनता के गहरे स्नेह और जुड़ाव का प्रतीक बन गईं। जनता-जनार्दन के दर्शन कर हुए अभिभूत बेदम जब कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, तो जय राम और जवाहर सिंह बेदम जिंदाबाद के नारों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो उठा। आयोजकों और गाँव के वरिष्ठ नागरिकों ने बेदम का माला पहनाकर और साफा बांधकर गर्मजोशी से स्वागत किया। मंच से विशाल जनसमूह को निहारते हुए बेदम ने हाथ जोड़कर और हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। उन्होंने इस अपार स्नेह को ‘जनता-जनार्दन का आशीर्वाद’ बताते हुए कहा कि यह दृश्य उनके सार्वजनिक जीवन की सबसे अनमूल्य धरोहर है।

हजारों की संख्या में मौजूद जनसमूह, विशेषकर रंग-बिरंगे परिधानों में, बैठी मातृशक्ति को संबोधित करते हुए बेदम ने अत्यंत भावपूर्ण लहजे में कहा, आज इस पवित्र मंच से मैं अपने पिता तुल्य बुजुर्गों, ऊर्जावान नौजवान साथियों और सती-सावित्री जैसी मेरी माताओं-बहनों को प्रणाम करता हूँ। उन्होंने कहा कि वह यहाँ एक मंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि एक बेटे और भाई के तौर पर इस पवित्र उत्सव में शामिल होने और आप सभी का आशीर्वाद लेने आए हैं। उन्होंने कहा, आपका यह विश्वास और स्नेह ही मुझे चौबीसों घंटे आपकी सेवा में जुटे रहने की असीम ऊर्जा प्रदान करता है। बेदम ने कहा कि वे केवल उत्सव में शामिल होने नहीं, बल्कि क्षेत्र के विकास का संकल्प पूरा करने भी आए हैं। उन्होंने जनसमूह की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच क्षेत्रवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करते हुए ‘पसोपा से नगला ढूंढी’ तक की सड़क के डामरीकरण को मंजूरी देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस सड़क का निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारंभ कर दिया जाएगा, जिससे दर्जनों गाँवों के लोगों को सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी।

गृह राज्य मंत्री बेदम ने कहा कि ये मेले हमारी प्राचीन संस्कृति और धार्मिक आस्था के जीवंत प्रतीक हैं। उन्होंने कहा, इन मेलों से हमारा सामाजिक ताना-बाना मजबूत होता है और आपसी भाईचारा बढ़ता है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि इन आस्था के केंद्रों का विकास और संरक्षण करना उनकी प्राथमिकता है और क्षेत्र के विकास में धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। बेदम ने अपने संबोधन में सभी क्षेत्रवासियों को पंच दिवसीय दीपोत्सव और विशेष रूप से भाई-बहन के पवित्र प्रेम के प्रतीक ‘भाई दूज’ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी। उन्होंने सभी की सुखी, स्वस्थ और समृद्ध जीवन की कामना करते हुए इस स्नेह और आशीर्वाद को संयव बनाए रखने की अपील की। कार्यक्रम का समापन एक भव्य और अविस्मरणीय पल बन गया, जब हजारों लोगों ने एक स्वर में मंत्री बेदम के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया।



सुविचार

सोच बदलो, दुनिया बदलेगी,
नकारात्मकता को दूर भगाओ।
हंसी, गाओ, जीवन को जीओ,
नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

महागठबंधन के सामने कितनी चुनौतियां?

महागठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी यादव को अपना उम्मीदवार घोषित कर ही दिया। हालांकि यह कोई अप्रत्याशित फैसला नहीं था। इस राज्य में कांग्रेस का मजबूत जनाधार नहीं है। वाम दलों की स्थिति उससे भी कमजोर है। विकासशील इन्सान पार्टी को दूसरे दलों के सहारे की दरकार है। बच गया राजद, तो उसके पास तेजस्वी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तेज प्रताप यादव खुद की पार्टी बनाकर अपनी ढफली पर अपना राग गा रहे हैं। तेजस्वी के चेहरे के साथ विधानसभा चुनाव लड़ रहे महागठबंधन के लिए कुछ फायदे हैं, तो कई चुनौतियां भी हैं। चुनावों में नए और युवा चेहरे को लेकर एक आकर्षण होता है। तेजस्वी को मैदान में लाकर महागठबंधन ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि हम युवाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लालू यादव के ये बेटे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर भले ही नए हों, लेकिन राजनीति में नए नहीं हैं। ये वर्ष 2010 से राजद के लिए खुलकर प्रचार कर रहे हैं। बिहार के उपमुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तेजस्वी यादव अपने भाषणों में राजद के परंपरागत वोटबैंक को साधने पर खासा जोर देते हैं। ऐसे कई इलाके हैं, जहां महागठबंधन को लालू यादव की राजनीतिक विरासत का फायदा मिल सकता है। वहीं, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जद (यू) के वर्षों से सरकार चलाने के कारण सत्ताविरोधी लहर होना स्वाभाविक है। तेजस्वी इसका फायदा उठाने की कोशिश भी कर रहे हैं। उनके समर्थक उन्हें भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखने लगे हैं। कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ गया है।

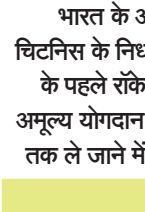
तेजस्वी यादव बिहार के लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए चाहे जितने बड़े वादे करें, वे राजद शासन के अनुभवों से पीछा नहीं छोड़ा सकते। मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग उस दौर को देख चुका है, जब राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। आम जनता लूट, हत्या, अपहरण, डकैती, रंगदारी से त्रस्त थी। उद्योगों ने बिहार छोड़कर अन्य राज्यों की राह पकड़ ली थी। आम लोगों के पलायन का सिलसिला आज तक जारी है। बिहार में कई मतदाता इसलिए भी राजद के खिलाफ वोट देते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि नव्हे के दशक का वही ‘जंगल राज’ लौट आए। लालू यादव के परिवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। चारा घोटाले ने लालू यादव की राजनीतिक छवि को काफी नुकसान पहुंचाया था। अब आईआरसीटीसी मामले में तेजस्वी यादव लपेटे में आ चुके हैं। इससे उनके विरोधियों को मौका मिल गया है। जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर उनकी शैक्षणिक योग्यता पर निशाना साधते रहते हैं। तेजस्वी हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का ऐसा वादा कर चुके हैं, जो राज्य की आर्थिक स्थिति के बूते से बाहर है। उन्होंने सभी संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने और जीविका दीदियों का वेतन 30 हजार रुपए प्रतिमाह करने की बात कहकर उम्मीदें जरूर जगा दी हैं, लेकिन इतना बजट कहां से आएगा, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। किसी भी राजनीतिक गठबंधन में दलों और नेताओं की महत्वाकांक्षाएं होती हैं। महागठबंधन में ऐसे कई नेता हैं, जो शिक्षा और अनुभव के मामले में तेजस्वी से बहुत आगे हैं। क्या वे उनका नेतृत्व स्वीकार करेंगे? यह एक बड़ा सवाल है। भाजपा और जन सुराज के नेता राजद के पिछले वादों की स्थिति और रिकॉर्ड को मुद्दा बनाकर खूब शब्दबाण छोड़ रहे हैं। तेजस्वी उनसे कितने सुरक्षित रह पाएंगे और उनका रथ तमाम बाधाओं को पार करेगा या बीच रास्ते में ही थम जाएगा – यह तो वक्त ही बताएगा। इतना तय है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में योद्धाओं के तरकश से ऐसे तीर निकलेंगे, जो पहले कम ही नजर आए थे।

ट्वीटर टॉक



महावीर चक्र से अलंकृत परम पूंज्य पिताजी स्वर्गीय ब्रिगेडियर महाराजा सवाई भवानी सिंह जी की जयंत की अवसर पर नाहरगढ़ स्थित जयपुर वैक्स म्यूजियम में उनकी मोम से बनी प्रतिमा का अनावरण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

-**दिव्या कुमारी**



भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के पुरोधा प्रो. एकनाथ वसंत चिटनिस के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। उन्होंने देश के पहले रॉकेट प्रक्षेपण से लेकर इसरो की नींव रखने तक अमूल्य योगदान दिया। अंतरिक्ष क्षेत्र में देश को नई उंचाइयों तक ले जाने में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा।

-**अशोक गहलोत**



दिल्ली प्रस्थान से पूर्व जोधपुर एयरपोर्ट पर जालोर विधायक एवं राज्य सरकार के मुख्य सचैतक श्री जोगेश्वर गर्ग से आत्मीय मुलाकात हुई। संयोगवश आज उनका जन्मदिवस भी है, जिसकी उन्हें हार्दिक शुभकामनाएँ दीं। जोधपुर शहर विधायक श्री अतुल भंसाली भी साथ रहे।

-**गजेन्द्र सिंह शेखावत**

प्रेरक प्रसंग

निःस्वार्थ पूजा

कौ रवों से जुए में अपना सब कुछ हारकर पांडव दर-दर की ठोकरें खा रहे थे। ऐसे में भी पांडव अपना धर्म-कर्म नहीं भूलते थे। एक दिन, जब युधिष्ठिर पूजा करके उठे, तो द्रौपदी उनके पास आई और कहने लगीं ‘महाराज, आप इतना भजन-पूजन करते हो, भगवान के निकट भी समझे जाते हो। आप भगवान से यह क्यों नहीं कहते कि वे हमारे संकट दूर कर दें?’ युधिष्ठिर सहजता से बोले ‘सुनो द्रौपदी, मैं परमात्मा का भजन किसी सौंदे के लिए नहीं करता। बल्कि यह भजन-पूजन तो मैं मन की शांति और आत्मिक आनंद के लिए करता हूं।

प्रकृति ने ये वन, पर्वत और नदियां बनाई हैं। हम इन्हें देखकर आनंदित होते हैं। ये जो कुछ भी देती हैं, वे स्वयं प्रदान करती हैं। इसी प्रकार, भगवान के भजन करके मैं स्वयं आनंदित होता हूं और उस समय उत्पन्न हुई प्रसन्नता ही मुझे परिस्थितियों से निपटने की क्षमता प्रदान करती है। यदि मैं अपने पूजा-पाठ के बदले भगवान से कुछ मांगूंगा, तो यह मेरी श्रद्धा नहीं, बल्कि भगवान से सौंदेबाजी होगी।’

DAKSHIN BHARAT RASHTRAMAT HINDI DAILY

सामयिक

‘संयुक्त राष्ट्र दिवस’ पर विशेष

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता

महेन्द्र तिवारी

मोबाइल : 9989703240

द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका ने मानवता को यह सिखाया कि शक्ति, युद्ध और साम्राज्य विस्तार के रास्ते अंततः विनाश की ओर ही ले जाते हैं। इसी अनुभव से जन्म हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ का, जिसने 24 अक्टूबर 1945 को यह संकल्प लिया कि आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की त्रासदी से बचाया जाए और विश्व में स्थायी शांति, सुरक्षा, विकास और सहयोग की नींव रखी जाए। लगाभग अस्सी वर्षों के इस लंबे सफर में संयुक्त राष्ट्र ने विश्व राजनीति, मानवाधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन जैसे अनगिनत क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। किंतु आज जब दुनिया फिर से विभाजन, ध्रुवीकरण और अनिश्चितता की ओर बढ़ रही है, तब यह प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या संयुक्त राष्ट्र अभी भी उतना ही प्रासंगिक है जितना इसे 1945 में बनाया गया था।

संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि उसने विश्व के लगभग सभी देशों को एक साझा मंच प्रदान किया। यह मंच संवाद, सहयोग और मध्यस्थता के जरिये संघर्षों का समाधान खोजने का अवसर देता है। महासभा में सभी देशों को समान मताधिकार प्राप्त है, जबकि सुरक्षा परिषद अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की देखरेख करती है। इसी संस्था के माध्यम से विश्व के अनेक हिस्सों में शांति स्थापना बल भेजे गए हैं, जिन्होंने युद्ध-विनाश लागू करवाने और मानवीय सहायता पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोरिया, कांगो, लेबनान, कंबोडिया, सूडान, सोमालिया, अफगानिस्तान, सीरिया और हाल के वर्षों में यूक्रेन व गाजा जैसे क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र की उपस्थिति किसी न किसी रूप में शांति और राहत की किरण लेकर पहुंची। मानवाधिकारों की रक्षा में भी संयुक्त राष्ट्र ने विश्व के नैतिक विवेक की तरह कार्य किया है। 1948 की मानवाधिकारों

की सार्वभौम घोषणा आज भी हर देश की संविधानिक संरचना और कानूनों को दिशा देती है। स्त्री अधिकार, बाल अधिकार, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, शरणार्थियों के संरक्षण और जातीय हिंसा पर अंकुश जैसे अनेक मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र ने ठोस नीतिगत और मानवीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।

सतत विकास की दिशा में 2015 में घोषित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी सतत विकास लक्ष्य, संयुक्त राष्ट्र की एक ऐतिहासिक पहल है, जिसका उद्देश्य गरीबी, भूखमरी, असमानता, लैंगिक भेदभाव, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय असंतुलन जैसी वैश्विक समस्याओं का समाधान करना है। इन लक्ष्यों ने विकास को केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित न रखकर उसे मानवीय और पर्यावरणीय संतुलन से जोड़ा।

कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) तथा अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने वैश्विक समन्वय, वैक्सीन वितरण और आपात राहत कार्यों में जो भूमिका निभाई, वह भी इस संगठन की प्रासंगिकता को रेखांकित करती है। इसी तरह जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों ने कार्बन उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा और हरित अर्थव्यवस्था की दिशा में वैश्विक प्रतिबद्धता को बल दिया है। फिर भी, इन उपलब्धियों के बावजूद संयुक्त राष्ट्र आज एक गहन संकट से गुजर रहा है।

सबसे बड़ा प्रश्न इसकी संरचना और निर्णय प्रक्रिया की निष्पक्षता से जुड़ा है। सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्य-अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन-वीटो शक्ति के माध्यम से किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं, चाहे उसके पक्ष में बहुमत ही क्यों न हो। इससे लोकतांत्रिक भावना को ठेस पहुंचती है और यह प्रतीत होता है कि संयुक्त राष्ट्र पर कुछ शक्तिशाली देशों का नियंत्रण है। उदाहरण के लिए, यूक्रेन या गाजा संकट में कई बार वैश्विक बहुमत होने के बावजूद एक वीटो ने मानवीय प्रस्तावों को ठुकरा दिया। यह

असमानता संगठन की विश्वसनीयता को कमजोर करती है।

इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र को वित्तीय संकट का भी सामना है। अनेक सदस्य देश समय पर अपने अंशदान नहीं देते, जिससे शांति अभियानों और मानवीय परियोजनाओं पर असर पड़ता है। कई बार संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टें और मिशनों पर राजनीतिक प्रभाव का आरोप भी लगाया जाता है, जिससे उसकी निष्पक्ष छवि पर प्रश्न उठते हैं। आज की दुनिया में एक और चुनौती उभर रही है-बढ़ती ध्रुवीकृत राजनीति और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्द्धिता, रूस-यूक्रेन युद्ध, मध्य-पूर्व का अस्थिर परिदृश्य और वैश्विक दक्षिण के देशों की आवाज को पॉप प्रतिनिधित्व न मिलना-ये सब दशांते हैं कि बहुपक्षीय सहयोग की भावना कमजोर हो रही है। तकनीकी असमानता, डेटा सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नैतिकता और डिजिटल दासता जैसे नए मुद्दे भी संयुक्त राष्ट्र के सामने जटिल प्रश्न बनकर उभरे हैं।

संयुक्त राष्ट्र को अपनी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और दक्षता बढ़ाने की आवश्यकता है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा आरंभ की गई यूएन80 पहल इसी दिशा में एक प्रयास है, जिसमें संगठन को आधुनिक, तकनीकी रूप से सक्षम और वित्तीय दृष्टि से स्वावलंबी बनाने की बात कही गई है। साथ ही, जी4 देशों-भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी-द्वारा सुरक्षा परिषद में विस्तार की माँग यह दर्शाती है कि विश्व अब एक नई प्रतिनिधित्व व्यवस्था चाहता है, जहाँ वैश्विक दक्षिण की आवाज भी निर्णायक हो।

भारत के दृष्टिकोण से संयुक्त राष्ट्र अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने न केवल शांति स्थापना अभियानों में सबसे अधिक सैनिक भेजे हैं, बल्कि मानवीय सहायता, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, शिक्षा और सतत विकास के अभियानों में भी अग्रणी भूमिका निभाई है। भारत का यह आग्रह कि सुरक्षा परिषद का स्वरूप वर्तमान वैश्विक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करे, पूर्णतः न्यायसंगत है। भारत का

उदय एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में संयुक्त राष्ट्र को भी एक संतुलित दिशा प्रदान कर सकता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि आज भी किसी बड़े संकट के समय विश्व की निगाहें उसी की ओर उठती हैं। चाहे युद्ध हो या महामारी, पर्यावरणीय आपदा हो या मानवीय संकट-संयुक्त राष्ट्र ही वह मंच है जहाँ सहमति की संभावना शेष रहती है। यह संस्था केवल सरकारों का समूह नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना की अभिव्यक्ति है, जो हर राष्ट्र, हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ी है। फिर भी, इस संगठन को अपने अस्तित्व और प्रभाव को बनाए रखने के लिए आत्मसुधार की राह पर चलना ही होगा। उसे वीटो की असमानता समाप्त कर अधिक लोकतांत्रिक और प्रतिनिधिक ढाँचा अपनाना होगा। वित्तीय पारदर्शिता, प्रशासनिक दक्षता और निर्णय प्रक्रिया में समानता लाने के बिना यह संस्था केवल प्रतीकात्मक रह जाएगी।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने बीते अस्सी वर्षों में मानव सभ्यता को कई बार विनाश के कगार से बचाया है, परंतु 21वीं सदी की चुनौतियाँ कहीं अधिक जटिल हैं-जलवायु संकट, वैश्विक महामारी, आर्थिक विषमता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नैतिकता और अंतरिक्ष व साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दे अब राष्ट्रीय सीमाओं से परे हैं। इनका समाधान केवल संयुक्त प्रयासों से ही संभव है, और यही वह बिंदु है जहाँ संयुक्त राष्ट्र की वास्तविक प्रासंगिकता निहित है। यदि यह संस्था अपने मूल उद्देश्य-विश्व शांति, मानव गरिमा और सामूहिक विकास-के प्रति फिर से प्रतिबद्ध हो सके, तो वह आने वाली सदी में भी मानवता की आशा बनी रह सकती है। संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता उसके भवनों, प्रस्तावों या सम्मेलनों में नहीं, बल्कि उस भावना में है जो कहती है-हम सब एक हैं, और हमारी सुरक्षा, हमारी शांति एक-दूसरे से जुड़ी हुई है। यही भावना इसे आज भी अपरिहार्य बनाती है, और यही इसे भविष्य में भी मानवता का सबसे सशक्त नैतिक मंच बनाए रखेगी।

नजरिया

बिहार चुनाव : मुद्दों एवं मूल्यों से दूर भागती राजनीति

तलित गर्ग

मोबाइल : 9811051133

बिहार में चुनावी रणभेरी बज चुकी है। हर दल अपने-अपने घोषणापत्र, नारों और वादों के साथ जनता को लुभाने में जुटा है। मंचों पर भाषणों की गर्मी है, प्रचार रथ दौड़ रहे हैं, लेकिन इस शोर में सबसे बड़ी कमी है-जनता के असली मुद्दों की आवाज। राजनीति का यह शोर विकास की असली जरूरतों को दबा रहा है। बिहार जैसे राज्य में जहां गरीबी, बेरोजगारी, अपराध, और सामाजिक पिछड़ापन अब भी विकराल रूप में मौजूद हैं, वहां चुनावी विमर्श का इनसे विमुख होना धिताजनक है। यह लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व चुनाव का विरोधाभास ही नहीं, दुर्भाग्य है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों बिहार चुनाव में कोई भी दल उन मुद्दों को ईमानदारी से नहीं उठा रहा जो सीधे-सीधे जनता के जीवन से जुड़े हैं? क्यों शराबबंदी, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, अपराध-माफिया और स्वास्थ्य जैसे वास्तविक सवाल राजनीतिक एजेंडे से गायब हैं?

बिहार में शराबबंदी एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा रहा है। यह मुद्दा केवल कानून का नहीं, बल्कि नैतिकता, सामाजिक सुधार और जनजीवन की स्थिती से जुड़ा हुआ है। शराबबंदी की सफलता या विफलता को लेकर जनता के मन में अनेक प्रश्न हैं, क्योंकि इस नीति ने जहां कई परिवारों को विनाश से बचाया, वहीं भ्रष्टाचार, अवैध तस्करी और पुलिसिया मनमानी को भी जन्म दिया। दिलचस्प यह है कि इस बार के चुनाव में लगभग सभी प्रमुख दल इस मुद्दे से दूरी बनाए हुए हैं। एनडीए खेमे के नेता खुलकर इस पर बोलने से बच रहे हैं। केवल प्रशांत कुमार जैसे कुछ नेता हैं जो पूर्ण शराबबंदी की पुनः स्थापना का नारा उठा रहे हैं। यह सवाल उठता है, अगर शराबबंदी सचमुच जनता के हित में थी, तो सत्ता पक्ष इससे डर क्यों रहा है? क्या यह स्वीकारोक्ति है कि कानून तो बनाया गया, लेकिन उसका क्रियान्वयन असफल रहा? शराबबंदी क्यों जरूरी है, उस महिला से पृष्ठिये, जिसकी बिछुए शराब पीने से लिये उसके पति ने बेच दी। ऐसी त्रासद घटनाएं बिहार के जन-जन में देखने को मिलती हैं।

वैसे तो हर एक का जीवन अनेकों विरोधाभासों एवं विसंगतियों से भरा रहता है। हमारा हर दिन भी कई विरोधाभासों के बीच बीतता है। आज तो हमारी सारी नीतियों में, हमारे सारे निर्णयों में, हमारे व्यवहार में, हमारे कथन में विरोधाभास स्पष्ट परिलक्षित है। लेकिन बिहार चुनाव ऐसे विरोधाभास के कारण कथनी करनी के अंतर का अखाड़ा ही बनते हुए प्रतीत होते हैं। यही कारण है कि हमारे जीवन में सच्य खोजने से भी नहीं मिलता। राजनेताओं एवं राजनीतिक दलों का व्यवहार दोगला हो गया है। उनके द्वारा दोहरे मापदण्ड अपनाने से हर नीति, हर निर्णय समाधानों से ज्यादा समस्याएं पैदा कर रहे हैं। चुनाव एवं चुनावी मुद्दे समस्याओं के समाधान का



आज बिहार को ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो चुनाव को जन-कल्याण के स्टिकोण से देखे, न कि केवल सत्ता प्राप्ति की दौड़ के रूप में। शराबबंदी, रोजगार, अपराध-मुक्ति, महिला सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे बिहार राज्य की आत्मा हैं। इन्हें नजरअंदाज़ करना, बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेलने जैसा है। विकास का अर्थ केवल सड़कें और पुल नहीं, बल्कि मानव विकास है, जहां हर व्यक्ति सुरक्षित, शिक्षित, रोजगारयुक्त और सम्मानजनक जीवन जी सके।

माध्यम बनने चाहिए, लेकिन वे समस्याओं को बढ़ाने का जरिये बनते रहे हैं। यही कारण है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महिला-सुरक्षा, अपराध-नियंत्रण की प्राथमिकता के नारे हमारे लिए स्वप्न ही बने हुए हैं।

ये तो कुछ नमूने हैं जबकि स्वतंत्रता के 78 वर्ष बाद भी हमें अहसास नहीं हो रहा है कि हम स्वतंत्र हैं। राजनीतिक विरोधाभासों और विसंगतियों से उत्पन्न समस्याओं से हम आजाद नहीं हुए हैं। हमारे कर्णधारों के चुनावी भाषणों में आदर्शों का व्याख्यान होता है और कृत्यों में भुला दिया जाता है। सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि हम हर स्तर पर वैश्वीकरण व अपने को बाजार बना रहे हैं। अपने को, समय को पहचानने वाला साबित कर रहे हैं। पर हमने अपने आप को, अपने भारत को, अपने बिहार को, अपने पैरों के नीचे की जमीन को नहीं पहचाना। नियति भी एक विसंगति का खेल खेल रही है। पहले जेल जाने वालों को कुर्सी मिलती थी, अब कुर्सी पाने वाले जेल जा रहे हैं। यह नियति का व्यंग्य है या सफर? पहले नेता के लिए श्रद्धा से सिर झुकता था अब शर्म से सिर

झुकता है। जिन्दा कौंमें पांच वर्ष तक इन्तजार नहीं करतीं, हमने 15 गुना इंतजार कर लिया है। यह विरोधाभास नहीं, दुर्भाग्य है, या सहिष्णुता कहे? जिसकी भी एक सीमा होती है, जो पानी की तरह गर्म होती-होती 50 डिग्री सेल्सियस पर भाप की शक्ति बन जाती है। बिहार इस नियति से कब मुक्त होगा, यही इस चुनावों में विमर्श का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए।

बिहार की सबसे बड़ी त्रासदी बेरोजगारी है। लाखों युवाओं के पास न काम है, न अवसर। हर चुनाव में इस पर वादे किए जाते हैं, लेकिन परिणाम लगभग शून्य रहते हैं। प्रदेश के नौजवान पलायन को मजबूर हैं, मजदूरी के लिए दूसरे राज्यों का रुख करते हैं। चुनावी सभाओं में नौकरियों का झंझा तो मिलता है, लेकिन ठोस योजनाएं और नीतियां कहीं दिखाई नहीं देतीं। राजनीतिक दलों के पास न तो रोजगार सृजन की दीर्घकालिक योजना है, न शिक्षा और कौशल विकास को जोड़ने की कोई ठोस रणनीति। चुनावी भाषणों में बिहार के विकास’ की बातें होती हैं, लेकिन युवा भविष्य की वास्तविक धिता कहीं नहीं

झलकती। बिहार में महिला सुरक्षा, अपराध और माफिया तंत्र का प्रश्न भी उतना ही ज्वलंत है। हाल के वर्षों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में लगातार वृद्धि हुई है। भूमि विवादों, रंगदारी और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अपराधियों की गतिविधियाँ अब भी जारी हैं। मगर किसी भी दल की ओर से इन पर कोई ठोस नीति या वचन नहीं दिखाई देता।

राजनीतिक दल जानते हैं कि इन विषयों पर बात करना असुविधाजनक है, क्योंकि यह सीधा शासन व्यवस्था की विफलता को उजागर करता है। इसलिए वे इन पर मौन साधे हुए हैं। अपराध और महिला सुरक्षा पर चुप्पी बताती है कि सत्ता प्राप्ति की होड़ में संवेदनशीलता की कोई जगह नहीं बची है। बिहार की राजनीति आज भी जातीय समीकरणों और तृष्णिकरण की जकड़ में फंसी हुई है। विकास और सुशासन की बातें केवल नारों तक सीमित हैं। उम्मीदवार घयन से लेकर प्रचार तक, हर जगह जातीय गणित प्राथमिकता में है। परिणाम यह है कि मुद्दे हाथिये पर चले जाते हैं और वोट बैंक की राजनीति सर्वोच्च शिक्षा पा लेती है। विकास के नाम पर किए गए बड़े-बड़े दावे चुनाव बीतते ही धुंधले पड़ जाते हैं। गांवों में आज भी सड़कें टूटी हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं, स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं, और प्रशासनिक तंत्र भ्रष्टाचार से त्रस्त है। ऐसे में जब राजनीतिक दल मुद्दों पर संवाद करने के बजाय केवल आरोप-प्रत्यारोप में व्यस्त हों, तो जनता का विश्वास कमजोर पड़ना स्वाभाविक है।

आज बिहार को ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो चुनाव को जन-कल्याण के दृष्टिकोण से देखे, न कि केवल सत्ता प्राप्ति की दौड़ के रूप में। शराबबंदी, रोजगार, अपराध-मुक्ति, महिला सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे बिहार राज्य की आत्मा हैं। इन्हें नजरअंदाज़ करना, बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेलने जैसा है। विकास का अर्थ केवल सड़कें और पुल नहीं, बल्कि मानव विकास है, जहां हर व्यक्ति सुरक्षित, शिक्षित, रोजगारयुक्त और सम्मानजनक जीवन जी सके। राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि जनता अब केवल नारों से नहीं, परिणामों से प्रभावित होती है। बिहार चुनाव हमें यह सोचने पर विवश करता है कि क्या राजनीति अब केवल सत्ता का खेल बनकर रह गई है? क्या लोकतंत्र का मूल उद्देश्य जनसेवा-अब खो गया है? जब जनता के असली मुद्दे, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और सामाजिक न्याय, चुनावी भाषणों से गायब हो जाएं, तब यह लोकतंत्र के क्षरण का संकेत है। जरूरत है कि राजनीतिक दल फिर से उन बुनियादी प्रश्नों पर लौटें, जिन पर बिहार का वर्तमान और भविष्य निर्भर करता है। यदि वे ऐसा नहीं करते, तो बिहार की जनता का यह चुनाव एक बार फिर केवल चेहरों और गठबंधनों का उत्सव बनकर रह जाएगा, जहाँ जनहित और जनसरोकार फिर से पीछे छूट जाएंगे। बिहार को नारों नहीं, नीतियों की राजनीति चाहिए और यह तभी संभव है, जब मुद्दों पर बात करने का साहस राजनीति में लौट आए।

महत्त्वपूर्ण

Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company,6/4 , 1st floor, Cantonment station road, Bengaluru-51and printed at Dinasadur Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekanth Parashar.** (*Responsible for selection of news under PRB Act).Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.RNI No. 58061/93. Regn No.: RNP/KA/BGS/2050/2015-2017 posted at Bengaluru PSO Mysore Road Bengaluru-560 026

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वरीकृत, टैंडर एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में सम्पत्त जानकारी यह स्वयं प्राप्त करें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उद्योगों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रण एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकते। — **दक्षिण भारत राष्ट्रमत**

